SHRI S.B. CHAVAN: Merely because you are able to shout, it does not necessarily mean that the merits of the case are going to change. They are not going to change merely because you are creating some kind of a noise here. I am sorry to say this. But in this particular case, it is a news item published by a newspaper, not given by the Government and so...*(Interruptions)*.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Do the Press people have a representative in the Cabinet meeting also? The Cabinet meeting is attended by Cabinet members. Apart from them, only the Cabinet Secretary is there. It is a high level. It is the top-most layer of administration. Even in such a meeting if a decision cannot be a guarded secret, if it is also leaked out, that only speaks of the present position of the Government. *(Interruptions)*.

SHRI S.B. CHAVAN: I think I have clarified the position. It is not the Government which has announced anything. If the Government has to announce, certainly, it will....*(Interruptions)*.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It was given to the Press deliberately to silence critics. *(Interruptions)*.

THE VICE-CHARIMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Das Gupta, the Home Minister is clarifying the position. Please listen to him. There is not point putting, again and again, the same question.

SHRI S.B. CHAVAN: The Government has not leaked out this information. If the Press people who were hovering around got some sort of information, I could not stop them from reporting. They have said, "from informed sources". How can I say what it is? They have not said how they got the information. But, I can inform hon. Members that I propose to consult the leaders of the Opposition tomorrow. Tomorrow, I am going to call the leaders of the Opposition from both the Rajya Sabha and the Lok Sabha. I am going to consult them on the new legislation which is on the anvil.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you, Mr. Minister. Now, we shall take up the clarifications regarding the Restricted Area Permit withdrawal.

Shri John Fernandes. Absent. Smt. Sushma Swaraj.

CLARIFICATION ON THE STATEMENT BY MINISTER—

Withdrawal of restricted area permit from Assam, Meghalaya and Tripura

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): धन्यवाद उपसभापति जी। आसाम, मेघालय और त्रिपुरा इन तीन राज्यों से रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हटाने के संबंध में गृह मंत्री द्वारा इस सदन में दिए गए वक्तव्य को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। इस वक्तव्य में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिनके संबंध में मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से स्पष्टीकरण लेना चाहूंगी। उपसभापति जी, मेरे और मंत्रीजी के बीच में एक मंत्री और एक सांसद आ खड़े हुए हैं, अब मैं कैसे देखूं मंत्रीजी को?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): साहू जी, आप अपनी सीट पर आ जाइए।

श्री रजनी रंजन साहू: सॉरी मैडम।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): But she has to address the Chair, Madam.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर सुनने वाला सामने दिखायी नहीं दे तो बोलने का फ्लो नहीं आता। वित्त मंत्रीजी आप दूसरे मामलों में बाधक हो रहे हैं तो इसमें भी हो रहे हैं?

गृह मंत्रीजी आपने इस वक्तव्य के प्रथम पैराग्राफ में तीन तरह के परमिट्स का जिक्र किया है— इनर लाइन परमिट जो कि भारतीयों को पूर्वोत्तर के चार राज्यों में जाने के लिए लेना पड़ता है और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट व रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जो कि विदेशी राष्ट्रिकों को पूर्वोत्तर के 7 अलग-अलग राज्यों में जाने के लिए लेना पड़ता है।

आपने केवल आर०ए०पी० हटाया है, वह रिस्ट्रिक्टिड एरिया परमिट जो विदेशी राष्ट्रिकों को असम, मेघालय और त्रिपुरा में जाने के लिए लेना पड़ता है, केवल उनके संबंध में आपने वक्तव्य दिया है और आपने उद्देश्य

बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने के लिए और पूर्वोत्तर के राज्यों के कबिलाई लोगों के गैर कबिलाई लोगों से तालमेल को बढ़ावा देने के लिए हमने आर०ए०पी० को हटाया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप केवल विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर में भेजना चाहते हैं? केवल विदेशी पूंजी निवेश को पूर्वोत्तर में चाहते हैं? केवल कबिलाई लोगों के विदेशी लोगों के साथ तालमेल को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्यों नहीं, आपने जब आर०ए०पी० को समाप्त करने की बात की, उस वक्त आई०एल०पी० यानी इनर लाइन परमिट, जो कि पूर्वोत्तर के बाकी चार राज्यों में लगा हुआ है, मुझे मालूम है कि अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में वह नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर के बाकी जिन चारों राज्यों में इनर लाइन परमिट लगा है वहां भारतीयों को भी उन राज्यों में प्रवेश करने के लिए परमिट लेकर जाने की जरूरत होती है, तो आप यह नीति बनाते समय इनर लाइन परमिट को खत्म करने की बात क्यों नहीं सोची? क्योंकि यह नीति कि भारतीयों पर पाबंदी और विदेशियों को छूट, यह नीति कैसे तर्कसंगत है, कैसे न्यायसंगत है, पहली जिज्ञासा मेरी यह है जो मैं आपसे जानना चाहती हूं? लेकिन यह एक अलग मुद्दा था, जो मेरे प्रमुख मुद्दे हैं, वह आर०ए०पी० के संबंध में हैं।

गृह मंत्री जी, जब हम किसी भी लगी हुई पाबंदी को हटाने की बात करते हैं तो एकमात्र कसौटी हमारे सामने यह होती है कि वे परिस्थितियां जो पाबंदी को लगाते वक्त मौजूद थीं, क्या आज समाप्त हो गई हैं? अगर जवाब मिलता है कि वे परिस्थितियां आज मौजूद नहीं हैं तो वह पाबंदी उसी क्षण हट जानी चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर वे परिस्थितियां मौजूद हैं तो फिर उस पाबंदी को हटाने का कोई औचित्य बनता नहीं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आपने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में तफ्सील की है। नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम और मणिपुर, जहां पी०ए०पी० लगा हुआ था विदेशी राष्ट्रिकों के लिए उसको आपने नहीं हटाया, लेकिन असम, मेघालय और त्रिपुरा में जो आर०ए०पी० लगाया हुआ था, वह हटाया है। इसके मायने यह है कि आप इन चार राज्यों को आज भी असुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी तुलना में आप इन तीन राज्यों को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस सदन में यह दावा कर सकते हैं कि असम आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिसके दरवाजे विदेशी नागरिकों के लिए खुल जाने में किसी तरह की कोई आपत्ति या किसी तरह की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आज भी उल्फा उग्रवादियों को विदेशी मदद, जो मेन बागी संगठन है असम का, आज भी उल्फा उग्रवादियों को क्या विदेशी मदद मिलने से रूक गई है? क्या यह सच नहीं है कि आज भी उल्फा उग्रवादियों का नेता ढाका में बैठकर के ऑपरेट कर रहा है? क्या यह सच नहीं है कि असम की समस्या की जड़ ही बंगला देश में है? और सबसे ज्यादा विदेशी घुसपैठ यदि पूर्वोत्तर के किसी राज्य में है तो वह असम में है? चाहिए तो यह था कि असम अकार्ड के तहत आपने जो वादा किया था वहां के लोगों से-बारबेड वायर फेंसिंग करने का, बॉर्डर को सील करने का, वक्त का तकाज़ा तो यह था कि आप असम के बॉर्डर की सीमाओं को सील करते, आप वहां बारबेड वायर फेंसिंग करते, लेकिन वह तो आप वादे से मुनकिर हुए सो हुए, आपने तो विदेशी राष्ट्रिकों के लिए 64 दरवाजे खोल दिए हैं। असम में कोई आए, कोई जाए, किस तरह की कोई रोक-टोक आपके इस आर०ए०पी० को हटाने के बाद रहेगी नहीं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं क्योंकि मुझे वहां की जॉगराफी और भूगोल के बारे में जानकारी है कि आपने नागालैंड से आर०ए०पी० इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आप समझते हैं कि नागालैंड में एन०एस०सी०एन० जैसा बागी संगठन आज भी सक्रिय है। लेकिन आप जानते हैं, असम का एकमात्र हिल-स्टेशन है हाफलॉंग और हाफलॉंग का सीधा रास्ता है नागालैंड से, वह सीधा अगर जुड़ा है किसी से तो नागालैंड से जुड़ा है। आपकी जानकारी में यह भी होगा कि आज पूर्वोत्तर में बागी गतिविधियों का केन्द्रालय, बागी गतिविधियों का मुख्यालय यह हाफलॉंग बना हुआ है। एक पूरा त्रिकोण देता है यह। सारी की सारी बागी गतिविधियों के सारे संगठनों के लोग अगर कहीं एक जगह पर सक्रिय हैं तो वह हाफलॉंग में हैं और हाफलॉंग से उनकी सारी बागी गतिविधियां चलती हैं और हाफलॉंग नागालैंड में नहीं है, गृह मंत्री जी, हाफलॉंग असम में है। असम से आर०ए०पी० हटाने के बाद क्या आप हाफलॉंग को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हाफलॉंग की गतिविधियां नागालैंड में सीधे-सीधे नहीं पहुंचेंगी? आर०ए०पी० हटाने के बाद क्या असम सुरक्षित रह पाएगा? क्या वहां पर जो उग्रवादी संगठन सक्रिय है, जो सीधे ढाका से ऑपरेट कर रहे हैं, वे और ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाएंगे? इसी तरह से मेघालय, आप जानते हैं मेघालय हिन्दुस्तान में यूरेनियम का सबसे सम्पन्न राज्य है और कितनी ही खबरें प्रकाश में आई हैं जहां यह पता लगा कि यूरेनियम की स्मगलिंग मेघालय से होती है। एक खबर तो यहां तक आई कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने वाला यूरेनियम

उसी नस्ल का है जिस नस्ल का यूरेनियम मेघालय से निकलता है। ऐसे यूरेनियम सम्पन्न राज्य को आपने आर०ए०पी० से मुक्त कर दिया। यानी कोई विदेशी नागरिक आए, कोई जाए। एक इतना बड़ा सेंशेटिव स्टेट और उसको केवल पर्यटन के नाम पर, केवल विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर आपने उसके दरवाजे खोल दिए। उदारीकरण के नाम पर आपने कहा कि कोई भी विदेशी आए, कोई जाए, बेलगाम वहां आ जा सकता है। इसी तरह त्रिपुरा, वहां पी०यू०जे० जैसे संगठन किस तरीके से सक्रिय हैं? वहां चकमा शरणार्थियों की किस तरह से समस्या बनी हुई है। आपने जो तीन राज्य चुने हैं वह तीन राज्य पूर्वोत्तर के सेंशेटिव राज्यों में सबसे ज्यादा हैं, बल्कि अगर सबसे पीसफुल कोई राज्य था तो वह मिजोरम था। उसमें तो आज भी आर०ए०पी० लगा हुआ है। लेकिन पूर्वोत्तर के तीन ऐसे संवेदनशील राज्य — आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, जो कि बागी गतिविधियों का मुख्यालय चलाते हैं, वहां से आपने आर०ए०पी० हटाने की बात की है। मैं आपसे पूछती हूं कि आर०ए०पी० में पाबंदी क्या थी? आर०ए०पी० में केवल यह पाबंदी भी कि जो फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन विजिटर्स आएगा, उसको अपने क्रेडेंशिएल्स बताने पड़ेंगे। जो उसका होस्ट होगा उसे उसके क्रेडेंशिएल्स बताने पड़ेंगे। और एक रूट — जिस रूट से वह जाएगा उसकी जानकारी उसको देनी होगी ताकि — (घंटी) — मैडम्, मैं समाप्त कर रही हूं। बल्कि हम एक-दो लोग ही बोलने वाले हैं। मैं घड़ी देखकर पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी।

लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। तो मैं आपसे यह कह रही थी कि आर०ए०पी० के तहत एक रूट की जानकारी देनी होती है। इन तीनों के रहते केवल एक मॉनिटरिंग मकेनिज्म था यानी आर०ए०पी० लोगों को मना किया जाता था। आर०ए०पी० जनरली मना नहीं किया जाता था। आप जब लिबरेलाइज करने की बात कर रहे थे, वह बात भी हमारी समझ में आती थी। अगर आप आर० ए० पी० को लिबरेलाइज कर दें यानी आर० ए० पी० देने में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती थी, उन दिक्कतों में आप ढिलाई करदें, यह भी बात समझ में आती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में पर्यटन बढ़े। हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में विदेशी पूंजी आए और भारतीय पूंजी आए। उसके लिबरेजाइजेशन तक तो बात समझ में आती थी। लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के बाद कौन सा मॉनिटरिंग मकेनिज्म आपके पास होगा? कोई आपको रूट की जानकारी नहीं देगा, कोई आपको कहां जा रहा है उसकी जानकारी नहीं देगा। कोई फॉरेन विजिटर आपको अपने केडेंशिएल्स नहीं बताएगा। सीधे आएंगे, सीधे जाएंगे, बे-लगाम और चौपट दरवाजे खुल जाएंगे। क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा आप पैदा नहीं कर रहे हैं? इसलिए मेरा अरोप है कि आर०ए०पी० समाप्त करने के बाद धर्मान्तरण को भी बढ़ावा मिलेगा। आर०ए०पी० समाप्त करने के बाद देश की सुरक्षा पर भी खतरा ज्यादा आएगा। पर्यटन आप, पूंजी निवेश हो लेकिन देश की सुरक्षा की कॉस्ट पर न हो, यह न आप चाहेंगे और न हम चाहेंगे। इसलिए मैं आपसे बहरहाल इस बात की अपील करना चाहूंगी कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आर०ए०पी० को लिबरेलाइज चाहें करदें, वहां तक हम आपके साथ सहमत हैं। लेकिन आर० ए० पी० को आप पूर्णतया समाप्त करेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। पहले ही रिपब्लिकन की यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट छप चुकी है। जहां उन्होंने कहा है कि आई०एस०आई० अब अपनी गतिविधियां कश्मीर और पंजाब से निकाल कर पूर्वोत्तर की तरफ ले जा रहा है और आप जानते हैं कि हाफ्लोंग में इस्लामिक लोग भी वहां से आकर के अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। आई०एस०आई० का भी यह बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। गृह मंत्री जी, इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करके उसका उदारीकरण चाहें करदें लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त करने की गलती बहुत बड़ी भूल, कल को यह हिमालयन ब्लंडर जैसी चीज कहलाएगी, इस भूल को आप दोबारा करने की कोशिश न करें। आर०ए०पी० को लिबरेलाइज करने तक हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसके पूर्णतया समाप्त करने में हमारा दल और मैं आपका विरोध करना चाहूंगी।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, my main point is this. The Standing Comittee on Transport and Tourism has recommended to the Government to leave this restriction. I have heard my colleagues, Shrimati Sushma Swaraj. When we have advanced in technology, when satellites can see even our backyards, I don't think we should be so much primitive as to restrict tourists to this inner line. To protect the interests of the tribals in the north-east, I feel that we can have some Constitutional provisions as we have article 370 in the case of Jammu and Kashmir to see that their lands are protected. At the same time, I

am for having a corridor, along the border, of 50 kilometres. I don't think we should be so dogmatic and restrict this area.

These are beautiful areas which our country can offer. In view of Jammu and Kashmir being out of bounds for tourists-the local tourists and international torists—these areas can be opened up to them. I would like to ask the hon. Home Minister whether he will also open up the other areas, the other States Like Mizoram, Nagaland and Tripura. There can be some Constitutional provision to protect the interests of the tribal peope.

SHRI HIPHEI (MIZORAM): Thank you, Madam, for giving me a chance to speak. Being an MP from North-East India, I would like to support the withdrawal of the RAP from some of the States in the North-East Region. There has been some objection. But if the visitors from abroad are not restricted to visit other parts of India, why should we restrict them from entering the North-East States?If there is not risk in the other parts of India, there will be no risk in North-East India also. Madam, the outlook of the Union Ministry, particularly, the Home Ministry, the way they are looking after the North-East States is contradictory in some respects. For example, the entry of foreign nationals into the North-Eastern parts of India is restricted. The issuing of passports to the Indians belonging to the North-East States is also restricted. He is restricted from going abroad. We have only one Regional Office at Guwahati. They have to first apply to Guwahati and after that for the application to reach Delhi it takes six months. After that, there is verification, police verification, and so many other verifications have to take place So, those who are willing to go abroad, those who want to go out of India, those who apply for passports are also facing problems. So, while considering lifting of the RAP, the issue of passport should also be considered. Instead of going to the Guwahati Regional Office, they should be able to apply at the capital of the State itself. Unless some special arrangment is made, we will face problems while applying for passports. I would like to add this suggestion. Otherwise, lifting of the RAP is welcome. Foreigners who are willing to visit the North-East States will not be willing to stay in the North-Easterm part of India for their lifetime. These visitors want to go back as soon as they finish their prupose of visit. Why should we restrict them. Today, we are demanding the retention of the ILP only because of the neighbouring country's nationals — the Bangladeshis. Now they are pouring in from across the border into Tripura, Assam and Mizoram.

They don't have any settlements. Once they come to Mizoram or Nagaland or Arunachal Pardesh, they don't like to go back to their country. Once I had to send some Chakma refugees, three thousand in number, when I was the Minister in the State of Mizoram. They all said that they would prefer to die in India rather than go back to Bangladesh. I told them that if they were going to die, they should go and die in their native country. It is far better. I told them that they should not die in a land which was not their native land. So, They were sent back to Bangladesh. We are surrounded by such kinds of people. That is why we are demanding for the retention of the Inner Line Permit. This is not to resist the entry of other Indian people from other parts of India. So, this has to be understood. This has to be accepted for the time being. A time will come when the people of the North Eastern States will understand that the Inner Line Permit should be lifted. Today the time is not yet ripe. So, I welcome the statement of the hon. Home Minister lifting the RAP in some of the States and retaining it in some other States. It has been my request, it has been our request that one of them should be retained and the other lifted. But in the considered view of the Home Ministry, they have decided that it is better to retain both the Permits. On

behalf of the people of Mizorm and on my own behalf, I congratualte the hon. Home Minister and also thank him. Thank you, Madam Vice-Chairman.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Madam, the hon. Ministers in charge of the Economic Ministries met in Shillong. Before the meeting, they had toured different States and decisions were taken on different issues. This was one of the issues which was discussed with the Chief Ministers. We also thought that it would be necessary that all the restrictions in the area should be removed. But the Chief Ministers of some of the States did object to this. In these three States, there was only the Restricted Area Permit. There seems to be some kind of confusion that terrorists are applying for the Restricted Area Permit. In fact, they don't require any permit. They just get in, infiltrate and make forcible entry. The RAP will apply only in the case of foreign nationals. All these permits are issued by different Embassies and by the four metropolitan cities in India so that we would be able to find out the people coming to these areas. Now having lifted all the restrictions in these three States, I think all those who come on visa will be required to take the RAP. hereafter, the RAP will not be required. On the basis of the visa, they can go to the respective States. The visa conditions are quite clear. The State Govenements are supposed to keep a watch on the activities of these people, especially the foreigners. There is not distinction between the domestic tourists and the foreigners who come as visitors to these areas.

The other point which was raised was about the Inner Line Permit. The Inner Line Permit was issued prior to independence, prior to the Constitution. But after the Constitutution—it is not know whether it is valid or invalide—this point is still pending in the Gawahati High Court. After we get the Court's decision, further action in the matter will have to be taken. Under the constitution, I don't think that we can restrict entry of any Indian cititzen to got to any part of India there should be complete freedom for any cititzen to go anywhere. But where tribals are living, there are clear instructions. About land alienation, there are clear instructions that land cannot be transferred to a non-tribal, If land is transferred to a non-tribal, then automatically such a stranfer becomes null and void. He does not get any rights. So, they need not have any fear that these people are going to stay over there because visas are issued to the foreigners either as piligrim visas or as tourist visas. All those people who visit these areas are for tourism purposes. So,, there is two-months visa, three-months visa, six-miniths visa, except for the students who come here for education—of course, their number is very restricted and those students get the visas. So, there is nothing wrong in reviewing the restrictions that we had under the RAP. In fact, beacuse of the RAP, it is not going to help us any more. We have other instruments in our hands and if nuclear material from Meghalay is tried to be smuggled outside India, we have some other laws under which we can definitely put restrictions and also take action against them and prosecute them. So also is the case regarding the insurgents or terrorists and their activities. In fact, they are not covered under this. If they go, as they have been going, against the prevalent law prosecutions have been launched against them, and hereafter also, because of lifting all this, there is not going to be any kind ofleniency towards allthose terrorists who are indulging in anti-national activities, Madam.

श्रीमती सुषमा स्वराजः मंत्री जी, आपने कहा कि टेररिस्ट इनफिल्ट्रेट करते थे। अब तो आपने उनका काम इतना आसान कर दिया कि अब उनको इनफिल्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे आएंगे और जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल तो है। आप यह मानेंगे कि सीधे आने से घुसपैठ के तौर पर आना मुश्किल तो है। अब तो ऐसा खुला दरवाजा है कि आओ और जाओ।

कोई आर०ए०पी० की जरूरत नहीं, कोई परमिट की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया किया है आपने।

SHRI HIPHEI (Mizoram): Madam, what about the passports? I would like to know whether there can be any simplified way of issuing passports. We are facing problems.

SHRI S. B. CHAVAN: I will convey your concern to the hon. Minister in charge of External Affaris and I am sure if these difficulties are being faced in the North-East, he will open more offices to issue the passports.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I am sure, the Members are satisfied with the reply given by the Home Minister. Now, there is the second clarification listed here and it is on the formation of Autonomous Hill Developmentcouncils for Ladak. Shri Ram Nath Kovind, please.

CLARIFICATIONS ON THE STATE URENT BY MINISTER FORMATION OF

Automonous Hil Development Councils for Ladak.

SHRI RAM NATH KOVIND (Uttar Pradesh): Madam, Chairperson, I am grateful to you for having given me the opportunity to seek clarfications on the statement made by the hon. Home Minister on the formation of the Autonomous Hill Development Councils for Ladakh.

Madam, I find from this statement that, in 1989, a tripartite agreement was entered into. that was the beiginning to bring in the present legislation. It is also on record that prior to 1989, the whole of Ladakh region had witnessed a turmoil and bloody violence which resulted in to the loss of thousands of lives and property. Madam, this statement is silent about what the Government has been doing since 1989. We all know that assembly elections are coming nearer. That is the reason why the Government acted so swiftly on a long pending demand. They have taken more than five years to bring about the present legislation and that too is a half-hearted attempt. This does not solve the problems which the whole Ladak region has been faced with. The statement says that this region had some special problems. Madam, we all know that the State Assemblies and Lok Sabha complete their term within a priod of five years. But, here is a case where the Governments has not been able to solve the problem of Ladakh region within a period of five years.They took more than five years for bringing about this legislation which is a half-hearted attempt. What have they done? They now propose to form a District Counci. As you know, there are two districts in the Ladak region. One is Ladakh and the other is kargil. The Government is going to constitute a District Council only for one district, i.e., the Ladakh District. This statement is also silent as to why the other district of Kargil is not being given a district council. Madam, I would like to seek some clarifications through you. Firstly, what prevented the Government from establishing a similar district council for the other district. Secondly, what will be the compostion and the number of constituencies in the district council, when both the district councils are not in existence, how the inter-district council could be formed and I would also like to know from the hon. Home Minister when he is going to constitute a district council Kargil District.

This statement also says that because of special circumstances and special problem the Government is going to form a District council and give autonomy. As we all know, the Jammu region has also been facing similar problems. there has been violence, there has been a pending demand from the prople of Jammu for autonomy. I would also like to know from the hon. Home Minister whether there is any proposal to form a separate autonomous council for the Jammu region. Madam, I would take one minute more.